Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LII (52), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक योजनाओं का प्रभाव – विशेष संदर्भ चंद्रपुर जिला

डॉ. राजेश्वर डी. रहांगडाले*

* सह-प्राध्यापक एवं प्रमुख (अर्थशास्त्र) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाविद्यालय, चिमूर, जिला-चंद्रपुर (महाराष्ट्र) भारत

शोध सारांश – चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का एक प्रमुख आदिवासी बहुल जिला है, जहाँ 34 विभिन्न आदिवासी जातियाँ (मुख्यत: गोंड – 80%) निवास करती हैं। जिले में आदिवासी जनसंख्या का अनुपात 17.07% है, जो राज्य की औसत से अधिक है। सरकार की विभिन्न आर्थिक योजनाओं (जैसे PM-JANMAN, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, एकाधिकार खरीदी योजना, शबरी आदिवासी वित्ता महामंडल ऋण) के माध्यम से आदिवासियों की आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह शोध पत्र माध्यमिक आँकड़ों (सरकारी रिपोर्ट, अध्ययन रिपोर्ट) पर आधारित है तथा इन योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव (आय वृद्धि, रोजगार अवसर) और चुनौतियों (जागरूकता की कमी, कार्यान्वयन में बाधाएँ) का विश्लेषण करता है। निष्कर्ष में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और स्थानीय भागीदारी बढ़ाने की सिफारिशें की गई हैं।

प्रस्तावना – चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र का सबसे बड़ा आदिवासी बहुल जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 3,89,267 आदिवासी थे (कुल जनसंख्या का 17.07%)। 2025 के अनुमान से यह संख्या 4.5 लाख से अधिक हो चुकी है। इसमें मुख्य रूप से गोंड, माडिया गोंड, कोलाम, परधान, हलबी, अंध आदि जातियाँ शामिल हैं। जिले के 1,673 गाँवों में से 850 से अधिक आदिवासी बहुल एवं दुर्गम हैं। ताडोबा-अंधारी टाइगर प्रोजेक्ट, कोयला खदानें और सीमेंट उद्योगों के कारण बड़ी मात्रा में जंगल और जमीन नष्ट हुई है, जिससे पारंपरिक आजीविका (वन उत्पाद संग्रहण, कृषि, पशुपालन) संकट में है।

राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों की प्रति व्यक्ति आय औसत से 65: से भी कम है और चंद्रपुर में यह और भी कम (लगभग रू 55,000-65,000 वार्षिक) है। 90% से अधिक आदिवासी परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। बड़े पैमाने पर पलायन (चीनी मिलों, ईंट भट्टों, निर्माण कार्य), कर्जदारी, कुपोषण (45% बच्चे कुपोषित), माध्यमिक स्तर पर 15-20% स्कूल ड्रॉपआउट जैसी समस्याएँ गंभीर हैं।

इस पृष्ठभूमि में केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक योजनाओं का उद्देश्य आदिवासियों को मुख्यधारा में लाना, स्वरोजगार सृजन करना और स्थायी आय स्रोत उपलब्ध कराना है। 2023 से PM-JANMAN और 2024 से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) शुरू हुआ है, जिसका सीधा प्रभाव चंद्रपुर के 167+PVTG एवं आदिवासी गाँवों पर पड़ रहा है। 2025-26 के केंद्रीय बजट में आदिवासी कल्याण के लिए 46% वृद्धि (रू14,925 करोड़) इस क्षेत्र की ओर बढ़ते ध्यान को दर्शाती है।

शोध पद्धति- यह शोध पूर्णत: माध्यमिक आँकड़ों पर आधारित है। निम्नलिखित विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग किया गया है:

- केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय वेबसाइट (http://tribal.nic.in/) एवं PIB रिलीज (जुलाई-अगस्त 2025)
- महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभाग (http://tribal.maharashtra.gov.in/) एवं महाशबरी महामंडल वेबसाइट (http://mahashabari.in)
- महाराष्ट्र बजट 2024-25 एवं 2025-26 विश्लेषण (PRS India, Economic Survey of Maharashtra 2024-25)
- चंद्रपुर जिला वेबसाइट (http://chandrapur.gov.in/) एवं ITDP चंद्रपुर के टेंडर/रिपोर्ट
- PIB, DD News, UNDP रिपोर्ट (2024-2025)
- शबरी महामंडल डैशबोर्ड (नवंबर 2025 तक)
- PM-JANMAN/DA-JGUA पोर्टल प्रगति डेटा (जून-अक्टूबर 2025)

विश्लेषण पद्धति- गुणात्मक परिमाणात्मक। 2018-19 से 2025-26 तक लाभार्थी संख्या, व्यय, प्रतिशत की तुलनात्मक जांच।

सीमा: प्राथमिक सर्वे नहीं होने से लाभार्थियों के प्रत्यक्ष अनुभव नहीं मिल सकेय केवल सरकारी आँकड़ों पर निर्भरता।

प्रमुख आर्थिक योजनाएँ

अ. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) / धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUAI) (2023-26)

कुल बजट: रू 24,104 करोड़ (केंद्र हिस्सा रू15,336 करोड़)

चंद्रपुर में 167 गाँव चयनित (माडिया गोंड बहुल)

प्रमुख घटक:PMAY-G घर, सड़कें, पेयजल, बिजली, सोलर, मार्केटिंग सेंटर, वन धन विकास केंद्र, होमस्टे, व्यवसाय प्रशिक्षण

नवंबर 2025 तक प्रगति: महाराष्ट्र में 70% से अधिक घर स्वीकृत, चंद्रपुर में 4,500 घर वितरण शुरू, 100 किमी सड़कें पूरी, 120 गाँवों में सोलर लाइटिंग।

ब. शबरी आदिवासी वित्ता एवं विकास महामंडल ऋण योजना (2024-

25 एवं 2025-26)

ब्याज दर:4-6%

अधिकतम ऋण: व्यक्तिगत रू5 लाख, स्वयं सहायता समूह रू15 लाख

2024-25 चंद्रपुर लक्ष्य: 2200+लाभार्थी

वास्तविक लाभ (नवंबर 2025 तक):1,989 नए लाभार्थी, रू60.56 करोड़ वितरित (राज्य स्तर); चंद्रपुर में 350+ लाभार्थी

मुख्य उपयोग: किराना दुकान, बकरी पालन, पोल्ट्री, सब्जी विक्रय, ऑटो रिक्शा।

क. एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना (ITDP) चंद्रपुर

16 उपकेंद्र, 128 गाँव

2024-25 खर्च: लगभग रू 520 करोड़

मुख्य कार्य : 100% अनुदान पर कुएँ, फार्म पाँड, पशुपालन किट, ड्रिप सिंचाई, सब्जी बीज

2025 में 19 आश्रमशालाओं/हॉस्टलों के लिए फूड सप्लाई टेंडर।

ड. एकाधिकार खरीदी योजना (तेंदू पत्ता):

2024 संग्रह: 5.80 लाख मानक बोरे, दर रू4800/बोरा

2025 बोनस: रू1500/बोरा चंद्रपुर-गडचिरोली-गोंदिया मिलाकर 12 लाख+ बोरे

85,000+ आदिवासी परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ (मई-जून 2025 में राशि वितरित।

इ. अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ :

वन धन विकास केंद्र: 15 केंद्र सक्रिय (महुआ, शहद, औषधी वनस्पतियाँ)

NSTFDC योजना: रू 10 लाख तक कम ब्याज ऋण

बिरसा मुंडा योजना: कृषि यांत्रिकीकरण अनुदान।

प्रभाव विश्लेषण:

सकारात्मक प्रभाव (2023-2025):

- PM-JANMAN से 4,500 परिवारों को घर, 80% गाँवों में सड़क-पानी-बिजली → पलायन में 15-20% कमी
- शबरी ऋण से 350 नए उद्योग→मासिक रू15,000-30,000 आय
- तेंदू पत्ता बोनस से रू120 करोड़ →85,000 परिवारों को नकद
- ITDP अनुदान से फसल उत्पादकता 35-40% वृद्धि
- औसत मासिक आय 2019 के रू4,500 से बढ़कर 2025 में रू 9,000-11,000

चुनौतिया/नकारात्मक पहलू:

- 40-45% लाभार्थियों को योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं
- दस्तावेज/आधार लिंकिंग के कारण 20-25% आवेदन रद्द
- खदानों से प्रभावित 15,000 परिवारों का पूर्ण पुनर्वास बाकी
- PM-JANMAN की गति धीमी (महाराष्ट्र में जून 2025 तक केवल 65-70%)
- शबरी ऋण वसूली 65%
- तेंदू पत्ता संग्रह में दलालों का हस्तक्षेप अब भी मौजूद।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें: 2023 से नवंबर 2025 तक चंद्रपुर में आदिवासी जीवन स्तर में स्पष्ट सुधार हुआ है। शबरी ऋण एवं तेंदू बोनस से नकद आय बढ़ी है, PM-JANMAN से मूलभूत सुविधाएँ मजबूत हुई हैं। फिर भी कार्यान्वयन में कमियाँ, जागरूकता की कमी और उद्योगों का नकारात्मक प्रभाव पूरी सफलता में बाधक हैं। 2025-26 में 46% बजट वृद्धि सकारात्मक संकेत है।

यदि नीचे दी गई सिफारिशें 2026 तक कड़ाई से लागू की जाएँ तो चंद्रपुर के आदिवासी परिवारों की औसत मासिक आय रू15,000-20,000 तक पहुँच सकती है और मजदूरी पलायन 60% से अधिक कम हो सकता है।

सिफारिशें:

1. गाँव स्तर पर मासिक जागरूकता शिविर अनिवार्य स्थानीय भाषाओं में डिजिटल माध्यम
   - हर तालुका में महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को संयुक्त शिविर
   - गोंडी, माडिया, हलबी, कोलामी में छोटे वीडियो/ऑडियो व्हाट्सएप से भेजें
   - आधार, बैंक, जाति प्रमाणपत्र की तत्काल जाँच/सुधार कैंप
2. PM-JANMAN/DA-JGUA के लिए अलग पूर्णकालिक विशेष अधिकारी त्रैमासिक फील्ड विजिट
3. शबरी ऋण प्रक्रिया पूर्णत% डिजिटल (15 दिन में पूरा) वसूली के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन
4. तेंदू पत्ता में 100% DBT बायोमेट्रिक हाजिरी दलालों पर स्थायी प्रतिबंध
5. प्रत्येक तालुका में 'आदिवासी उद्यमिता एवं कौशल विकास केंद्र' (बकरी/मुर्गी पालन, महुआ प्रसंस्करण, सोलर तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग आदि प्रशिक्षण)
6. हर साल स्वतंत्र तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन (TISS/IIM/Gokhale Institute द्वारा)
7. अतिरिक्त सिफारिशें
   - सीमेंट/कोयला कंपनियों के SR से स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सोलर प्लांट अनिवार्य
   - आदिवासी महिलाओं के लिए 'लक्ष्मी बचत गट' - रू 20 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण
   - वन अधिकार दावों का जून 2026 तक 100% निपटारा।

इन सभी सिफारिशों को यदि 2026 के बजट में कार्य-योजना के साथ शामिल किया जाए तो चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र का 'आदिवासी विकास मॉडल जिला' बन सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Times of India (2024), PM's tribal upliftment scheme to reach 167 Chanda villages.
2. Burghate, K., &Herkal, S. (2023). TIJER.
3. Galaxy International Multidisciplinary Research Journal (2024).
4. Proceedings ICHES (2024).
5. TRTI Evaluation Reports (2019-2021).
6. IIP Series (2024).
7. Tribal Maharashtra Annual Report (2018-19).

****